unfortunately, I cannot agree with the hon. Member. Scrap is an important item and it has to be imported spending our precious foreign exchange. There was pressure in this House, through a Calling-Attention motion, because of difficulties felt by the electric are furnaces and the secondary sector. Government has gradually reduced the customs duty on scrap from 15 to 5 per cent. At the same time, Government has also given the benefit of these shipbreaking facilities so that the people who use scrap get scrap at a competitive price. This has helped many people to open their units which were closed. Now what the hon. Member is saying is that some of the old types of secondary sector units using scrap are in difficulties. The Standing Committee on Industry has submitted a report, enumerating the difficulties and suggesting certain remedies. We have formed a small group in our Ministry. The report has come before me, and after studying it we will come before the Cabinet and Parliament and we shall take care of the situation which is there, but not by stopping ship-breaking. The shipbreaking industry in Gujarat is doing extremely well and helping the country. They are buying ships at very low rates and supplying scrap.(Interruption).... Let me finish. In 1993-94, the shipbreaking industry produced 1.2 million tonnes of scrap, and in 1994-95 it was 2.06 million tonnes. Thereby they are saving foreign exchange. You are talking of some new industries. Today, the electric are furnances have to change. The outdated blast furnances and others are not effective now: We know they are job-oriented, and that is why we have reduced the customs duty. But the point you have raised is also in our mind. The Standing Committee on Industry whose Chairman, Dr. Ashok Mitra is here—has submitted a report and we are examining it. We will take steps, but not by stopping the import of ships and breaking them. By other methods we will try to help them.

श्री शिवचरण सिंहः मान्यवर, शिप्स स्क्रेप जो आ

रहा है, उसमें बडा घोटाला है। शिप में कई दूसरी चीज़ें भी होती हैं। उनकी वजह से यह शिप्स स्क्रेप जो आ रहा है, लोहा आ रहा है, उसको सस्ता बेचा जाता है। उनमें जो दसरे मेटल होते हैं जैसे कॉपर होता है. लेड होता है, ब्रास फिटिंग्ज़ होती है, सोना-चांदी कई चीज़ों में मिक्स होता है। उस स्क्रेप के नाम से इम्पोर्ट लाइसेंस देते हैं और फायदा उठाते हैं दूसरी चीज़ों से तथा आयरन स्क्रैप को सस्ता बेचते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir. I cannot answer this.

*85. [The Questioner (Shri Govindrao Adik) was absent. For answer vide col. 34 infra. I

राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा प्रतियोगिता योजना

- *86. श्री ईश दत्त यादवः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) राष्ट्रीय खेलकुद प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं:
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का राज्यवार न्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकल वासनिक): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

- (क) राष्ट्रीय खेलकद प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—
 - (1) खेलों को प्रारंभिक स्तर पर बढावा देना और 8-12 आयु वर्ग के बच्चा के बीच खेलों में भाग लेने के लिए खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना.
 - (2) ऐसे प्रतिभाशाली लड़कों और लड़कियों का पता लगाना जिन्हें प्राकृतिक प्रेरक गृण और शारीरिक विकास आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुए

(3) चुनिदा बच्चों को वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

(ম্ব)	इस योजना वे	अधीन गत	तीन वर्षी	के दौरान
सरकार ने	निम्नलिखित	राशि प्रदान	की:	

(1)	1992-93	407.84 ला	स्त्र रू॰	•
(2)	1003-04	400 40 MI	H Ko	•

- (2) 1993-94 499.69 लाख रू॰ *
- (3) 1994-95 449.76 लाख रू॰ (अनित्तम)

(ग) वर्तमान में इस योजना को विभिन्न राज्यों / संघ

शासित क्षेत्रों में स्थित 47 अपनाए गए स्कूलों में लागू किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:—

1992-93	1185
1993-94	1241
1994-95	1268

राज्यवार आंकड़े विवरण-क में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

इस योजना के अंतर्गत दाखिल किए गए अनेक बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जूनियर और उप-जूनियर चैम्पियनशिप में श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया।

विवरण-क

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	1992-93	1 99 3- 9 4	1 994-9 5
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	53	57	44
2.	मध्य प्रदेश	32	48	46
3.	राजस्थान	42	31	24
4.	उत्तर प्रदेश	103	98	81
5 .	चंडीगढ़	60	59	52
6.	हरियाणा	89	97	101
7.	पंजाब	21	23	24
8.	जम्मू व कश्मीर	7	·	
9.	हिमाचल प्रदेश	· ·	6	6
10.	आन्ध्र प्रदेश	81	88	67
11.	कर्नाटक	38	39	44
12.	तमिलनाडु	39	64	41
13.	केरल	32	55	27
14.	गोवा	9 .	_	23
15.	महाराष्ट्र	105	85	107
16.	गुजरात	30	23	13
17.	बिहार	72	48	126
18.	उड़ीसा	46	42	42

^{* (}इसमें आर्मी बाल खेल कपनियों के खर्चे भी शामिल है)

1	2	3	4	5
19.	पश्चिम बंगाल	161	177	178
20.	सिकिम	18	30	27
21.	मेघालय	31	22	26
22.	मणिपुर	21	26	31
23.	नागालैप्ड	22	25	9
24.	असम	62	59	78
25.	त्रिपुरा	9	. 30	20
26 .	अरूणाचल प्रदेश	1	9	31
	अखिल भारत जोड़ः	1185	1241	1268

श्री ईश दत्त यादवः मान्यवर सभापति जी, राष्ट्रीय खेलकुद प्रतिभा प्रतियोगिता के मंत्री जी ने तीन विशेषताएं बतायी हैं—8 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों में खेलों के प्रति जागति पैदा करना, प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाना और इन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण देना। लेकिन मान्यवर, हमारे प्रश्न के भाग ''ख'' और ''ग'' के संबंध में जो उन्होंने उत्तर दिया है इससे स्पष्ट है कि इतने बड़े देश में जहां करोड़ों बच्चे इस आयु वर्ग के होंगे और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन सबको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीन वर्षों के आंकडे मंत्री जी ने दिए है। 1992-93 में 1185, 1993-94 में 1241 और 1994-95 में 1268 बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है या मिल रहा है और ऐसे बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है। इनके ऊपर धन भी बहत कम व्यय किया जा रहा है। 1992-93 में 407.84 लाख रुपए 1993-94 में 499.69 लाख और 1994-95 में 449.76 लाखा। इस वर्ष तो और कम कर दिया है पिछले वर्षों की अपेक्षा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हं कि क्या इस योजना का आप विस्तार करने का विचार कर रहे हैं ताकि देश में जो करोड़ों प्रतिभावान स्रात्र इस आयु वर्ग के हैं खेल कृद में जिनकी रुचि है जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं वे बच्चे भी इस योजना का लाभ पा सकें? इस योजना के लिए आप अधिक धन व्यय करने का प्रावधान करने जा रहे हैं अथवा नहीं?

SHRI MUKUL WASNIK: Sir, it is true that this Scheme covers only a limited number of schools and a limited number of children. The intention of the Scheme is not that it should reach every

school, but that it should reach those schools which have got some basic sports facilities. They have an interest in developing sports and they are keen to admit students primarily for sports purposes also.

But, I do agree with the hon. Member when he says that a large number of students should be covered. With this in mind, we have already had discussions with the Kendriya Vidyalaya Sangathan and the Navodaya Vidyalaya Sangathan. The Kendriya Vidyalayas are about 850 while the Navodaya Vidyalayas are around 400. We are trying to see that the coaches of the Sports Authority who have been deployed in the District Coaching Centres, should spend a considerable time in these schools so that the children in these schools are benefited. We are also working on some schemes to be undertaken with these institutions.

Sir, not a large number of students have been covered under the Scheme. Even then, the fact is that quite a number of the students who have been trained under the NSTC Scheme have shown remarkable performances at the junior and sub-junior levels in national competitions and some have also done well in some international sub-junior competitions also. There are some strengths of the Scheme and we are trying to see that whatever we can do

200

more towards promoting the Scheme will be done in the coming days.

श्री ईंग दत्त यादवः मान्यवर सभापति जी. इसमें कम बच्चों का चयन होता है। मैं मंत्री जी की बात से संतृष्ट हं कि ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, जितने बच्चों का भी चयन किया जाता है जिसको मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हं, इसके बारे में आरोप यह है कि जो चयन की प्रक्रिया है यह दोषपूर्ण है. इसमें पक्षपात किया जाता है। मैं मंत्री जी से ञानना चाहता हं कि कया आपके पास या आपके विभाग के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि जो सही ढंग से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए वह नहीं अपनायी गयी है और सही चुनाव नहीं हुआ है, इस तरह का आरोप मिला है या नहीं? मिला है तो आपने आंच किया या नहीं? यदि जांच किया है तो कार्यवाही क्या की गई है? मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन यह होगा माननीय मंत्री जी से कि क्या आपके पास इस प्रकार के कोई आंकड़े हैं कि इस चुनाव में या इस चयन में तीन वर्षों के अन्दर शहर के कितने बच्चों का चुनाव हआ है और गांव के कितने बच्चों का चुनाव हआ है? मान्यवर, मेरी यह जानकारी है और मेरा एक तरह से यह आरोप भी है कि केवल प्रभावशाली लोगों के बच्चे. जिनके परिवार प्रभावशाली हैं और शहर में ही रहते हैं जिनका असर पहुंच जाता है उनके बच्चों का इसमें चयन कर लिया जाता है और जो देहात और गांव के रहने वाले प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका चयन नहीं हो पाता है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह की शिकायत मिली है और आपके पास कोई आंकडे हैं या नहीं कि तीन साल के अन्दर शहर के कितने बच्चे चुने गए और गांव के कितने बच्चे चुने गए?

SHRI MUKUL WASNIK: Earlier in the scheme, the children used to be selected by watching their performances. But later on a battery of tests were evolved. Based on a battery of tests like speed, strength, endurance, explosive power, coordination, agility as well as various other activities including the aptitutde of the child, they are selected. things are taken these consideration. A test has been developed and strictly based on these tests the children are selected. There is no partiality because partiality may benefit an individual. But the scheme is being run to develop young talented children

so that they can participate and perform well in international competitions in the years to come. Therefore, there is no partiality. A few complaints have come to me. It is not that no complaints have come. But on very rare occasions complaints have come. We examined those complaints. But generally I can say that this selection procedure has been implemented in the right spirit. We are trying to see that...

SHRI JANESHWAR MISRA: What is the ratio of rural and urban areas?

SHRI MUKUL WASNIK: That figure we have not collected. I do not have the figure, but the scheme is open for rural as well as urban children. We have seen a large number of rural children who have joined the scheme. There are a large number of rural children who are doing very well in the sports arena.

श्री ईश दत्त यादवः आप आंकड़े बताइये?

श्री मुकुल वासनिकः आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि उस तरह के आंकड़े हम लोगों ने नहीं लिए हैं। इसमें किसी भी तरह से अर्बन और रूरल का विभाजन नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ उन बच्चों का चयन होता है जो खेल के क्षेत्र में आगे अपनी प्रतिभा बढ़ा सकते हैं।

श्री कैलाश नारायण सारंगः विभाजन का सवाल ही नहीं है, आपने गांवों को इयोअर किया है, इसलिए विभाजन का प्रश्न हीं नहीं है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्रः यह गलत बात है। आप किसी बुनियाद पर यह बात नहीं कह रहे हैं।

SHRIMATI CHANDRIKA
ABHINANDAN JAIN: Thank you very
much, Sir. We have sports loving
Ministers in Madhavrao Scindia and
Mukul Wasnikji. Both of them are very
active cricketers and they participate in
the Members of Parliament cricketing
event whenever we have cricket matches.
Unfortunately, sports is getting a low
priority in the country. The intentions
are very good, but the efforts are not
enough. For example, the budgetary
provision for sports is not even 0.001 per
cent.



SHRI SURESH KALMADI: It went down.

SHRIMATI CHANDRIKA
ABHINANDAN JAIN: Suresh Kalmadiji
is also endorsing my views that it went
down. For this particular scheme, where
we are spotting the talents all over the
country, only Rs. 4.5 crores are reserved
for talent scouting activities. Sir, I would
request both these Ministers, through
you, that they must try to augment our
budget for sports in general, not
necessarily for this particular scheme.

Sir, I would like to cite the example of Miss Charushila Naigaonkar. She is a marathon runner. She belongs to Nagpur. She runs bare-footed. She doesn't have shoes to take part in the marathon event. What about these types of sportsmen and sportswomen who cannot even afford shoes? Would you like to come up with a scheme to provide basic facilities to the sports people who have reached national and international levels? They do not have proper facilities to train' themselves. Are you going to come up with a scheme, particularly for women, where you will provide these facilities to them?

SHRI MUKUL WASNIK: Sir, first of all......

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Neglect of Tribal Welfare in Andhra Pradesh

- *82. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that ITDA in West Godavari has enumerated the number of tribals in Tallavaram Village in Polavaram Mandal (Andhra Pradesh) who have been totally ignored;
- (b) if so, how many such tribals are there in Tallavaram who have never

- received any assistance for the last 10 years from ITDA;
- (c) if so, what action is proposed to enquire into this neglect; and
- (d) the steps taken to assist such tribals in Tallavaram who have been totally ingored?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a). The Mandal Prajaparishad Development Officer, Pollavaram, has taken up a survey of families with a view to provide suitable assistance under poverty alleviation programme.

(b) to (d) Tallavaram, a hamlet of Kondrukota village, has 122 Scheduled Tribe families out of whom 116 were assisted to construct houses in 1986. 58 S.T. families have been assisted for horticultural development and 3 S.T. families for carpentry units.

Command Area Development Programme

- *85. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:
- (a) whether it has come to the notice of Government that the "Command Area Development Programme" widely acclaimed important and as an indispensable device for bringing the irrigation potential created under optimum utilisation with better water management techniques has been relegated to secondary importance due to the failure to achieve physical target;
- (b) if so, whether the very purpose of enhancing agricultural productivity and production through optimum and scientific use of scarcely available water resources has been defeated; and
- (c) if so, the reaction of Government thereon and the steps taken to improve the situation?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA):